भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3304

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए शिक्षा समानता

3304. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
डॉ. भोला सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसदीय स्थायी समिति और नीति आयोग द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 में शामिल करने की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा को इससे बाहर रखने के कारण क्या हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा को शैक्षिक समानता प्रदान करने और अन्य आयुष प्रणालियों के समान एक समर्पित विनियामक ढांचा स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के 4 सितंबर 2006 के दिशानिर्देशों और प्राकृतिक चिकित्सा कार्य बल (2009) की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए कोई केंद्रीय या राज्यस्तरीय परिषद गठित की गई है, या इस संबंध में कोई प्रस्ताव या रूपरेखा विचाराधीन है; और

(ङ) क्या सरकार प्रशिक्षित और पारंपरिक प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों की अद्यतन राष्ट्रीय रजिस्ट्री रखती है, जिसमें दशकों से सेवा दे रहे चिकित्सक भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (आईएमसीसी अधिनियम, 1970) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020) द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चूँकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आईएमसीसी अधिनियम, 1970 का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 में शामिल नहीं किया गया। हालाँकि, आयुष मंत्रालय योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर कार्यरत है और इसने एक शीर्ष केंद्रीय अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है।

(ख) से (ङ): अन्य आयुष पद्धतियों के समान समर्पित नियामक ढांचा स्थापित करने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। हालांकि, आयुष मंत्रालय ने योग प्रमाणन बोर्ड

(वाईसीबी) की स्थापना की है जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के अधीन काम कर रहा है और योग पेशेवरों को प्रमाणित करने और योग संस्थानों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के तत्वावधान में स्थापित प्राकृतिक चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (एनआरबी) प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों के केंद्रीय पंजीकरण और प्राकृतिक चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को मान्यता दिए जाने के लिए जिम्मेदार है। एनआरबी संस्थागत रूप से प्रशिक्षित बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बीएनवाईएस) स्नातकों को पंजीकृत करता है, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त की है। आज तक, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वाले 523 बीएनवाईएस स्नातक एन आर बी के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। केंद्रीय पंजीकरण के अतिरिक्त, वर्तमान में 15 राज्य स्तरीय परिषदें कार्यरत हैं जो अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण का कार्य करती हैं।

*****